ceased fully. No further studies were considered necessary.

Wind Power Projects in the Country

*416. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many wind power projects are there presently in the country, alongwith their generation capacity and actual generation during 1995-96;

(b) the number of such projects in Madhya Pradesh, with their generation capacity and actual generation;

(c) whether any cost comparison on wind power vis-a-vis solar power generation is available;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether running/recurring cost on solar power generation is much less; and

(f) if so, the reasons for not setting up of more solar plant manufacturing facilities and power projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER & MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) A total wind power capacity of 818 MW has been installed in the country at 36 locations in 8 States. Over 1.7 billion units have been fed to the respective State grids from these projects so far. Of this, about 500 million units were generated during 1995-96.

(b) A total capacity of 8 MW has been established at two locations in Madhya Pradesh, 0.59 MW at Kheda and 7.43 MW at Jamgodarani. Nearly, 8 million units have been generated from these projects so far.

(c) and (d) Firm comparative cost figures are not available for wind power vis-a-vis solar power as no large scale commercial solar power projects have been established in the country so far. The cost of generation from wind power projects varies from Rs. 2.00-2.50 per KWh depending upon the site and taking into account the various incentives available.

(e) The capital cost of Solar Power Projects are expected to be higher than the capital cost of wind power projects. However, the running cost of wind power and solar power projects is comparable as reurring fuel cost is not involved in both the cases.

(f) does not arise.

Recommendationss of P. Murari Committee

*417. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to answer to Unstarred Question 143 given in the Rajya Sabha on the 21st November, 1996 and state:

(a) the details of the recommendations of the P. Murari Committee accepted by Government;

(b) whether the problem of Indian fishermen has been overcome with the implementation of the recommendations; if so, the what extent;

(c) whether it is a fact that there is some legal impediment in cancelling the licences of MNCs given by Government in deep sea fishing; and

(d) if so, the stand taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (d) All the recommendations of the Review Committee on Deep Sea Fishing Policy have been accepted by the Government in principle.

Action has already been initiated to implement the recomendations of the Review Committee. The recommendations regarding further restricting the fishing areas of deep sea fishing vessels operating under Charter and New Deep Sea Fishing Policy, 1991 will lead to availability of larger area for exploitation by traditional fishermen and mechanised boat operators. Other recommendations relating to training and assistance to traditional fishermen for taking up deep sea fishing and recommendation regarding extending/ strengthening continuing activities like infrastructure development etc. will also be beneficial to the traditional fishermen.

No licences have been granted to MNCs. However, one of the recommendations of the Review Committee suggested immediate cancellation of all permits issued for fishing by Joint Venture, Charter, Leasing, and Testing Fishing subject to legal processes as may be required. It has been decided that these permits can be cancelled only for violation of the provisions of the MZI Act, 1981 or any rule or order made thereunder and/or the conditions stipulated in the approvals granted. Action for cancellation or otherwise of such approvals has to be decided in individual cases in consultation with the Ministry of law, accordingly.

अमरनाथ त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा राशि

*418. **श्रीमती आनंदी ज॰ पटेल:**
श्री राघवजी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरनाथ यात्रा, 1996 के दौरान कितने तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर गए:

(ख) उक्त यात्रा के दौरान कितने तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई तथा कितने तीर्थयात्रियों के तापता होने की सूचना मिली:

(ग) कितने मृत तीर्थयात्रियों के परिवारजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजा-राशि प्राप्त हो गई है:

(घ) जिन परिवारजनों को अभी तक मुआवजा-राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें यह कब तक प्रदान कर दी जाएगी उन्हें मुआवजा-राशि प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण है:

(ङ) तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है: और

(च) भविष्य में ऐसी दु:खद घटना को न होने दे के लिए सरकार द्वारा कौन-कोन से कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) लगभग 1.2 लाख तीर्थयात्रियों ने 1996 की अमरनाथ यात्राा में हिस्सा लिया।

(ख) यात्रा के दौरान 243 तीर्थयात्री मारे गए थे और उपलब्ध सूचना के अनुसार 2 व्यक्तियों को गिनती में नहीं लिया गया।

(ग) और (घ) दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के निकटतम संबंधी को 2 लाख रूपये की अनुग्रह राहत अदा की जानी है। पहचान लिए गए 147 मृतकों के संबंध में अनुग्रह राहत की राशि जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उन संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दी गई थी जिन राज्यों से वे लोग संबंधित थे। गैर-शिनाखत-शुदा व्यक्तियों के संबंध में, मृत तीर्थयात्रियों के फोटोग्राफ विभिन्न राज्य सरकारों को भेजे गए थे और जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सलाह दी गई थी कि उक्त दर से धन राज्य सरकारों को शिनाख्त होते ही भेज दें। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया था कि वे उस जिले के जिला कलक्टर जिस जिले से मृतक संबंधित था, के माध्यम से मृतक के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राहत का संवितरण करें। अभी तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा जम्मू एवं कश्मीर के स्थानीय प्रशासन को इस प्रयोजन हेतु 2.94 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

(ङ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, पहलगाम और पवित्र गुफा पर तम्बुओं, कंक्रीट शैडों, खाद्यानों, चिकित्सा सहायता शिविरों कंबलों, टेलीफोन सुविधाओं, बेतार नेटवर्क, ईंधन की लकड़ी एल पी जी सिलिंडरो, पशु चिकित्सा केन्द्रों, टट्टुओं, मजदूरों, बड़े जनरेटरों, पोर्टेबल अग्निशन उपकरणों की व्यवस्था की थी। इसके अलावा "अलावा योग्य" एवं "न करने योग्य" कार्यों एवं यात्रियों के लिए जरूरी मूलभूत जानकारी काफी पहले ही मुद्रित एवं प्रकाशित की गई थी ताकि सामने आने वाली मौसमी कठिनाइयों को मद्दे नजर यात्रियों को मार्गदर्शन मिल सके। पिछले वर्षों में उग्रवादियों की ओर से यात्रा के लिए खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध भी किए गए थे।

(च) सरकार ने डा॰ नितीश कुमार सेनगुप्ता की नियुक्ति, अमरनाथ यात्रा दुर्घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतू जांच अधिकारी के रूप में की थी। डा॰ सेनगुप्ता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार के परामर्श से और जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार, भविष्य में अमरनाथ यात्राओं को सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त उपाय किया जाना सुनिश्चित करेगी।